Australian Government Department of Education | Australian Government Department of Employment and Workplace Relations | Ministry of Education Government of India | कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद (Australia-India Education and Skills Council) की तीसरी मीटिंग

संयुक्त विज्ञप्ति

निम्न पक्षों के बीच -

ऑस्ट्रेलिया सरकार का शिक्षा विभाग (Department of Education) एवं रोजगार एवं कार्यस्थल संबंध विभाग (Department of Employment and Workplace Relations)

और

भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) एवं कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship)

8 दिसंबर 2025

नई दिल्ली, भारत

प्रस्तावना

1. मंत्रीगण ने शिक्षा, कौशल और शोध में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद (AIESC) की मुख्य द्विपक्षीय मंच के रूप में पुन: पुष्टि की। AIESC 2024 मीटिंग में हुई चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, दोनों पक्षों ने छह कार्यनीतिक आधारशिलाओं पर गहरा सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई: जिसमें सीमापार शिक्षा, विनियामक सहयोग, कुशल कार्यबल विकास, स्कूली शिक्षा, खेल संबंधी शिक्षा और शोध सहयोग शामिल हैं।

2. मंत्रीगण ने भारत द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020 (NEP)) को लागू करने के प्रति अपनी साझी प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि की , जिसे 2047 तक Viksit Bharat (विकसित भारत) के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक परिवर्तनकारी ढांचे के तौर पर मान्यता दी गई है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि NEP द्वारा विश्वव्यापी पहुँच, गुणवत्ता, समानता और अंतर्राष्ट्रीयकरण को महत्व देना काफी हद तक शिक्षा, कौशल और शोध में ऑस्ट्रेलिया के सामर्थ्य से मिलता-जुलता है।

3. वर्ष 2025 में भारत की NEP लागू होने के पांच साल पूरे होने के अवसर पर, मंत्रीगण ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा एवं कौशल साझेदारी में आपसी सहयोग को बढ़ाने में इसकी भूमिका पर ध्यान दिया। हमारी संस्थानों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और छात्रों के सार्थक आदान-प्रदान से आपसी सहयोग में विस्तार हुआ है। यह प्रबल साझेदारी शिक्षा एवं कौशल के माध्यम से राष्ट्र और व्यक्तिगत समृद्धि के लिए साझी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

सीमापार शिक्षा

4. मंत्रीगण ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटियों के कैंपस की स्थापना जारी रखने का स्वागत किया, जिसमें डीकिन यूनिवर्सिटी (Deakin University), यूनिवर्सिटी ऑफ़ वॉलोन्गॉन्ग (University of Wollongong), यूनिवर्सिटी ऑफ़ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया (University of Western Australia), वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी (Western Sydney University), विक्टोरिया यूनिवर्सिटी (Victoria University), ला ट्रोब यूनिवर्सिटी (La Trobe University) और यूनिवर्सिटी ऑफ़ न्यू साउथ वेल्स (University of New South Wales) द्वारा की गई प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं।

5. मंत्रीगण ने उच्च शिक्षा में पहुँच, समानता और गुणवत्ता के लिए कार्यनीतिक सक्षमकर्ता के तौर पर ऑनलाइन और ब्लेंडेड (मिश्रित) डिलीवरी पर ज़ोर दिया, जो भारत की NEP 2020 और विकसित भारत 2047 के उद्देश्य का समर्थन करती है। 2023 पारस्परिक मान्यता क्रियाविधि (2023 Mutual Recognition Mechanism) के आधार पर, उन्होंने डिजिटल शिक्षण एवं गुणवत्ता आश्वासन में ऑस्ट्रेलिया के सामर्थ्य का लाभ उठाने वाले स्केलेबल मॉडल पर सहयोग करने की सहमति दी और संस्थागत साझेदारी और छात्र पहुँच को बढ़ाने के लिए भारत द्वारा SWAYAM से सम्बन्धित ऑस्ट्रेलियाई कोर्स की अनुमति देने की सराहना की।

6. मंत्रीगण ने गतिशीलता, रोजगार योग्यता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए दोहरी योग्यता को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि की। उन्होंने संस्थागत साझेदारियों को बढ़ावा देने पर सहमति प्रकट की, और RMIT–BITS पिलानी के विस्तार मॉडल की सफलता पर ध्यान दिलाया, जो प्राथमिकता क्षेत्रों में मापनीयता और प्रभाव को दर्शाते हैं। मंत्रीगण ने संस्थागत संबंधों को गहरा करने और कार्यबल में योगदान देने वाले इन पहलों के महत्व पर ज़ोर दिया, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक, ज्ञान-संचालित अर्थव्यवस्थाएँ बनाने के लिए साझा प्रतिबद्धता प्रबल होती है।

विनियामक सहयोग

7. मंत्रीगण ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन को आगे बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की **टर्शियरी शिक्षा गुणवत्ता और मानक एजेंसी (Australia's Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA))** और भारत की **यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन** (**University Grants Commission (UGC)**) के बीच गहरी भागीदारी का समर्थन किया। इसमें उच्च शिक्षा नवाचार में सर्वोत्तम अभ्यास पर संयुक्त प्रयास और नई चुनौतियों से निपटना शामिल है, जैसे शिक्षण और सीखने में जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को शामिल किया जाना। मंत्रीगण ने विनियामकों को नवाचार का समर्थन करने के लिए

सर्वोत्तम प्रथाएँ और विनियामक ज्ञान साझा करने का काम सौंपा, जिसमें शैक्षणिक अखंडता की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना शामिल है।

8. मंत्रीगण को **ऑस्ट्रेलियाई कौशल गुणवत्ता प्राधिकरण (Australian Skills Quality Authority (ASQA))** और **भारत की राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (India's National Council for Vocational Education and Training (NCVET))** के मध्य विस्तारित सहयोग की आशा है। इसमें सीमापार व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (VET) डिलीवरी पर सहयोग, प्रशिक्षक विनिमय कार्यक्रम, योग्यताओं के संयुक्त विकास में सहायता, ब्रिजिंग कोर्स और गुणवत्ता आश्वासन उपकरणों एवं क्रियाविधियों पर ज्ञान और व्यावहारिक आदान-प्रदान शामिल हैं। इस साझेदारी से पोर्टेबल, उद्योग-प्रासंगिक योग्यताओं के विकास और विनियामक व्यवस्थाओं और प्राथमिकताओं की आपसी समझ को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

कुशल कार्यबल विकास

9. मंत्रीगण ने आर्थिक विकास और कार्यबल परिवर्तन के लिए शिक्षा सहयोग की भूमिका को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में फिर से दोहराया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले प्राथमिक क्षेत्रों के लिए कुशल, अनुकूलनीय कार्यबल बनाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय संस्थानों के मध्य साझेदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

10. मंत्रीगण ने शिक्षार्थियों और पेशेवरों के लिए सरल मार्ग बनाने की अहमियत को स्वीकार किया और ऑस्ट्रेलियाई संस्थानों में भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए मौजूदा और नई छात्रवृत्ति योजनाओं तक बेहतर पहुँच बनाने पर सहमति जताई, विशेष रूप से व्यावसायिक एवं एप्लाइड कौशल कार्यक्षेत्रों में। दोनों पक्षों ने मौजूदा ढ़ांचे की समीक्षा करने तथा अधिक जागरूकता और उपयोग को बढ़ावा देने पर सहमति जताई, ताकि सीमापार शिक्षा को सशक्त बनाया जा सके, सीखने की प्रगति में मदद की जा सके और लोगों के मध्य संबंधों को गहरा किया जा सके।

11. मंत्रीगण ने कृषि में महत्वपूर्ण कौशल विकास (Developing Critical Skills) परियोजना की सफलता की सराहना की। उन्होंने परियोजना के माइक्रोक्रेडेंशियल्स को भारत के केंद्रीय विकास केंद्र नेटवर्क के साथ जोड़ने, भारत में ऑस्ट्रेलियाई कैंपसों में कोर्स प्रदान करने और SWAYAM पर माइक्रोक्रेडेंशियल्स के माध्यम से छात्रों की पहुँच बढ़ाने की योजनाओं पर बात की।

12. मंत्रीगण ने रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र के लिए कौशल विकास को प्रोत्साहना देने में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते सहयोग को स्वीकार किया। उन्होंने सौर टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज और इससे संबंधित नए कार्यक्षेत्रों में भविष्य के रिन्यूएबल कार्यबल के लिए कौशल प्रशिक्षण को अपग्रेड करने के प्रयासों की सराहना की। दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि बेहतर कौशल सहयोग से सुस्थिर भविष्य के लिए कुशल कार्यबल को विकसित करने में मदद मिलेगी।

13. मंत्रीगण ने लक्षित परियोजनाओं के लिए **ऑस्ट्रेलिया-भारत कार्यबल भविष्य पहल** (**Australia–India Workforce Futures Initiative**) के प्रति प्रतिबद्धता जताई, जिसमें कार्यबल पूर्वानुमान, अंतराल प्रशिक्षण और खेल, प्रारंभिक बाल्यावस्था तथा माइनिंग क्षेत्र में पायलट परियोजनाओं के साथ R&D कार्यबल विकास शामिल है, ताकि नौकरी की भूमिकाओं की मैपिंग (पहचान और वर्गीकरण) की जा सके,

योग्यताओं को संरेखित किया जा सके और व्यावसायीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। ये प्रयास साझा आर्थिक प्राथमिकताओं पर प्रतिक्रिया देने वाली संस्थागत और उद्योग साझेदारी के विकास में मदद करेंगे।

14. मंत्रीगण ने **औद्योगिक-शैक्षणिक साझेदारी** पर भी ज़ोर दिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया-भारत CEO फोरम (Australia-India CEO Forum) साझेदारी भी शामिल है, ताकि कोर्स और योग्यताओं को नियोक्ता के साथ मिलकर तथा कार्यबल की माँग के अनुरूप बनाए जाना सुनिश्चित किया जा सके। इन प्रयासों को भविष्य के कार्यबल की आवश्यकताओं के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रीगण ने जॉब्स एंड स्किल्स ऑस्ट्रेलिया (Jobs and Skills Australia) एवं NCVET के माध्यम से कार्यबल पूर्वानुमान की आवश्यकता को दोहराया, ताकि संस्थाएँ **कौशल अंतराल का अंदाज़ा लगा सकें और** उसी के अनुरूप **शिक्षा के मार्ग डिज़ाइन कर सकें**।

15. मंत्रीगण ने उद्योग-आधारित शिक्षा के पारस्परिक लाभों पर बात की और प्राथमिक क्षेत्रों में भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और ऑस्ट्रेलिया के TAFEs के मध्य साझेदारी और कार्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित किया। इस संदर्भ में, मंत्रीगण ने वार्षिक भारत-ऑस्ट्रेलिया कौशल बैठक (Annual India–Australia Skills Meet) के आयोजन का भी वादा किया, जो दोनों देशों में बारी-बारी से होगा और जो वर्ल्डस्किल्स कॉम्पिटिशन के अनुरूप VET (TAFEs के साथ मिलकर) में संस्थागत साझेदारियों, कौशल इकोसिस्टम संरेखन, और विनिमय पर ध्यान केंद्रित करेगा, ताकि युवा प्रतियोगियों को प्रेरित किया जा सके, कौशल को आकांक्षात्मक बनाया जा सके, और कौशल उत्कृष्टता के लिए मानक निर्धारित किए जा सकें।

16. दोनों मंत्रियों ने रोजगार योग्यता मैट्रिक्स पर सहयोग की संभावना की खोज पर सहमति जताई, ताकि इसे नौकरी की तैयारी के विश्वसनीय और मानकीकृत उपाय के तौर पर उपयोग किया जा सके और इसके साथ ही उन्होंने, शक्षार्थियों, नियोक्ताओं, नीति निर्माताओं और बड़े पैमाने पर पुनः कौशल प्रयासों की मदद के लिए माइक्रो-क्रेडेंशियल्स की अनुकूलनशीलता और स्टैकेबिलिटी (चरणबद्ध रूप से जोड़ी जा सकने वाली योग्यताओं) पर भी बातचीत की।

स्कूल एवं शिक्षक शिक्षा

17. मंत्रीगण ने समावेशी, उच्च गुणवत्ता वाली प्रणाली बनाने में प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं स्कूली शिक्षा की बुनियादी भूमिका की दोबारा पुष्टि की। उन्होंने भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education (CBSE) के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रमाणपत्र (अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सर्टिफिकेट) और ऑस्ट्रेलिया के प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में प्रमाणपत्र III (सर्टिफिकेट III इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन) के बीच तुलनात्मक पाठ्यक्रम विकसित कर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई, इससे मापनीय अंतराल प्रशिक्षण प्रदान करते हुए भारत के प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यबल को प्रबल किया जाएगा।

18. मंत्रीगण ने ऑस्ट्रेलियाई शिक्षण एवं और स्कूल नेतृत्व संस्थान (Australian Institute for Teaching and School Leadership (AITSL)) और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (the National Council for Teacher Education (NCTE) द्वारा **शिक्षण मापनों की मैपिंग (मिलान करने)** की सराहना की, और इसे शिक्षक की शिक्षा में गहरी संस्थागत साझेदारी के लिए आधारशिला माना, जिसमें शिक्षकों के लिए दोहरी योग्यता का सह-विकास और पायलटिंग शामिल है। इस प्रगति को आगे बढ़ाते हुए, मंत्रीगण ने AITSL और NCTE के मध्य निरंतर सहयोग की प्रोत्साहना की और शिक्षक की शिक्षा में सहयोग को प्रबल करने के लिए आगे के लेन-देन और सहयोगात्मक गतिविधियों पर विचार किया।

19. मंत्रीगण ने उत्तर प्रदेश में मोनाश यूनिवर्सिटी की टीचिंग एक्सीलेंस अकैडमी (Monash University's Teaching Excellence Academy) को मास्टर शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और शिक्षण गुणवत्ता में व्यवस्थित सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया-भारत संस्थान द्वारा अग्रणी भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई साझेदारों के साथ मिलकर शिक्षकों के लिए बनाई गई टूलकिट की भी सराहना की, जो भारतीय शिक्षकों को साक्ष्य-आधारित संसाधन देती है। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि माइक्रोक्रेडेंशियल्स और ऑनलाइन डिलीवरी पेशेवर विकास के लिए मापनीय मॉडल प्रदान करते हैं और उन्होंने भारतीय शिक्षकों की ऑस्ट्रेलियाई संसाधनों तक पहुँच बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई।

20. इसके साथ ही, मंत्रीगण ने ऑस्ट्रेलिया में **CBSE वैश्विक पाठ्यक्रम** की डिलीवरी को सक्षम बनाने में सहयोग देने पर सहमति जताई, जिसे CBSE और प्रासंगिक ऑस्ट्रेलियाई शैक्षिक प्राधिकरणों के मध्य परामर्श की सुविधा प्रदान करके, विनियामक और गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं पर जानकारी साझा करके, और CBSE एफिलिएशन के लिए संभावित ऑस्ट्रेलियाई स्कूलों तक पहुंच का समर्थन प्रदान कर पूरा किया जाएगा। दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से सहमत किसी भी गतिविधि पर विचार करेंगे, जिससे ऑस्ट्रेलिया में CBSE मान्यता प्राप्त स्कूल स्थापित किए जा सकें।

खेल संबंधी शिक्षा और शोध

21. मंत्रीगण ने आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और द्विपक्षीय जुड़ाव के संचालक के तौर पर खेल संबंधी शिक्षा और शोध के कार्यनीतिक महत्व को भी स्वीकार किया। मंत्रीगण ने इस क्षेत्र में बढ़ती नीति, साझेदारी और आर्थिक गति की सराहना की। ऑस्ट्रेलिया की खेल कूटनीति 2030 कार्यनीति (Australia's Sports Diplomacy 2030 strategy) और भारत के 'खेलो भारत मिशन (Khelo Bharat Mission)' में प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करते हुए, मंत्रीगण ने खेल में बेहतरीन प्रदर्शन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए खेलों में शिक्षा और शोध साझेदारी के अवसरों पर बात की।

22. मंत्रीगण ने **ऑस्ट्रेलिया-भारत खेल शिक्षा और शोध वेबिनार** सीरीज़ के पूरा होने की सराहना की, जो खेल संबंधी शिक्षा, शोध और कार्यबल विकास में पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने के लिए कार्यनीतिक प्लेटफॉर्म है। इस सीरीज़ में खेल पाठ्यक्रम डिजाइन, खेल उद्योग साझेदारी, उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन और शिक्षण नवाचार में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की विशेषज्ञता के बारे में दिखाया गया है। मंत्रीगण ने यह बताया कि इस पहल से खेल संबंधी शिक्षा में क्षमता और उत्कृष्टता बनाने के लिए 400 से अधिक लोग एक साथ आए, इसके साथ ही संस्थागत साझेदारियों और जानकारी के लेन-देन को भी बढ़ावा दिया गया।

23. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 2032 ओलंपिक्स और पैरालिंपिक की मेजबानी करने वाला है और भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और संभवत: 2036 ओलंपिक्स की भी मेजबानी करने वाला है, इसलिए मंत्रीगण ने इस बात पर ध्यान दिया कि ऑस्ट्रेलिया भारत को उसकी खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन और निर्माण कार्यबल तैयार करने में मदद कर सकता है। मंत्रीगण ने खेल विज्ञान और प्रशिक्षण में ऑस्ट्रेलिया की निपुणता पर भी ध्यान दिया, जो खेल निर्माण में भारत की निपुणता का पूरक हो सकता है।

24. इस जुड़ाव की गति का लाभ उठाते हुए, मंत्रीगण ने संस्थानों को दोहरी योग्यता के अवसरों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो खेल उद्योग की माँग को पूरा करेंगे। **ऑस्ट्रेलिया-भारत कार्यबल भविष्य पहल** (**Australia-India Workforce Futures Initiative**) के तहत खेल उद्योग के लिए कार्यबल

पूर्वानुमान, संस्थागत साझेदारी के माध्यम से भारत के भविष्य के खेल कार्यबलों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्राथमिक नौकरी की भूमिकाओं की मैपिंग (मिलान) के लिए टेस्टबेड (प्रयोगात्मक मंच) के रूप में काम करेगी।

25. मंत्रीगण ने शारीरिक साक्षरता, छात्र कल्याण और सक्रिय जीवनशैली में आजीवन जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में खेल शिक्षा को शामिल करने के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई पाठ्यक्रम, आकलन एवं रिपोर्टिंग प्राधिकरण (ACARA) और राष्ट्रीय शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के बीच और अधिक जुड़ाव का समर्थन किया, ताकि NEP 2020 में बताए तरीके के अनुसार, स्कूली शिक्षा के लिए **खेल शिक्षा पाठ्यक्रम** को लागू करने में मदद मिल सके। मंत्रीगण ने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए **खेल शिक्षा में शिक्षकों के पेशेवर विकास** की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया और संस्थानों को इस उद्देश्य को पूरा करने वाली साझेदारी के अवसर खोजने के लिए प्रोत्साहित किया।

26. मंत्रीगण ने उत्कृष्टता, वहनीयता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए समग्र खेल इकोसिस्टम बनाने के महत्व पर ज़ोर दिया, जिसमें खेल संबंधी शिक्षा और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य जागरूकता, बायोमैकेनिक्स और डेटा ड्रिवन मोशन एनालिसिस सहित खेल विज्ञान, कोचिंग और एथलीट समर्थन प्रणाली, और संस्थागत सहयोग को शामिल किए जाने पर बातचीत की गई।

27. मंत्रीगण ने नवाचार और प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए खेल शोध में गहरे सहयोग का समर्थन किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय संस्थानों को खेल निकायों के साथ साझेदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि एथलीट विकास, कोचिंग विज्ञान, चोट की रोकथाम और सामुदायिक भागीदारी में साझा प्राथमिकताओं को संबोधित किया जा सके। ये साझेदारियाँ शैक्षणिक शोध को व्यावहारिक परिणामों में बदलने में मदद करेंगी, खेल संबंधी शिक्षा के लिए साक्ष्य आधार को बढ़ाएंगी, और व्यावसायीकरण के अवसरों को बढ़ावा देंगी।

28. मंत्रीगण ने खेल और शारीरिक स्वास्थ्य क्षेत्र में संरचित सहयोग के महत्व पर ज़ोर दिया, और इसे उभररे हुए उद्योग के तौर पर पहचाना जिसमें रोजगार की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं और यह भारत की GDP में लगभग 2% योगदान दे सकता है। उन्होंने खेल प्रबंधन और खेल प्रौद्योगिकी में ऑस्ट्रेलिया के वैश्विक नेतृत्व को खेल निर्माण में भारत की बढ़ती ताकत और खेल प्रबंधन में गिग अर्थव्यवस्था (अस्थायी रोजगार अर्थव्यवस्था) का पूरक बताया।

शोध सहयोग

29. मंत्रीगण ने नवाचार, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के संचालक के तौर पर ऑस्ट्रेलिया-भारत शोध साझेदारी के महत्व की पुष्टि की, जिसमें व्यावसायीकरण, बदलाव और कुशल शोध कार्यबल बनाने पर ध्यान दिया गया। उन्होंने व्यावहारिक सहयोग को निर्देशित करने के लिए **ऑस्ट्रेलिया-भारत शोध सहयोग ढ़ांचे** (**Australia–India Research Collaboration Framework**) की सराहना की और संस्थानों और शोधकर्ताओं को जोड़ने के लिए **ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ता सहयोग केंद्र भारत (ARCH-भारत) (Australian Researcher Cooperation Hub India (ARCH-India))** प्लेटफॉर्म के महत्व की पुन: पुष्टि की।

30. मंत्रीगण ने इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर तक साझी पहुँच, नवाचार फंडिंग, और शैक्षणिक शोध में उद्योग की भागीदारी के ज़रिए गहरे सहयोग को प्रोत्साहित किया। उन्होंने संयुक्त डॉक्टरेट कार्यक्रमों, प्रारंभिक-करियर आदान-प्रदानों और परामर्श योजनाओं के ज़रिए शोधकर्ता गतिशीलता और क्षमता निर्माण के महत्व पर ज़ोर दिया। मंत्रीगण ने माइनिंग (खनन), रिन्यूएबल एनर्जी और महत्वपूर्ण खनिजों में शोध के लिए तैयार कार्यबल बनाने और नवाचार को वास्तविक दुनिया में उपयोग करने से जुड़ी पहलों पर ध्यान दिया।

31. ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय की भूमिका को पहचानते हुए, मंत्रीगण ने **ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के शिक्षाविदों के फोरम** (**Forum of Academics of Indian Origin in Australia**) की सराहना की, जो ज्ञान के आदान-प्रदान, अंतःविषय सहयोग और परामर्श के लिए एक प्लेटफॉर्म है। मंत्रीगण ने अधिकारियों को फोरम को भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई उद्योगों से जोड़ने का काम सौंपा, इसे फोरम के सदस्यों के विशेष ज्ञान और शोध एवं विकास के प्रयासों से लाभ मिल सकता है।

32. उन्होंने शोधकर्ता गतिशीलता को प्रबल करने के लिए **भारत की शैक्षणिक एवं शोध सहयोग को बढ़ावा देने की योजना (Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration (SPARC))** को एक महत्वपूर्ण प्रणाली के तौर पर स्वीकार किया और द्विपक्षीय शोध परिणामों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर जुड़ाव को प्रोत्साहित किया।

समापन

33. मंत्रीगण ने व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और स्कूलों, कौशल और उच्च शिक्षा पर लगातार तीन-तरफ़ा ध्यान देते हुए, 2026 में ऑस्ट्रेलिया में अगली AIESC मीटिंग के आयोजन पर सहमति जताई।